

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, अलीगढ, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

कूष्माण्डेति चतुर्थकम्

‘ओम ऐं ह्रीं क्लीं
कूष्मांडायै नमः’



लौकी, कढ़ू गोलाकार है। अतः यहाँ इसका अर्थ प्राणशक्ति से है – वह प्राणशक्ति जो पूर्ण, एक गोलाकार, वृत्त की भाँति है। भारतीय परंपरा के अनुसार लौकी, कढ़ू का सेवन मात्र ब्राह्मण, महा ज्ञानी ही करते थे। अन्य कोई भी वर्ग इसका सेवन नहीं करता था। लौकी, कढ़ू आपकी प्राणशक्ति, बुद्धिमत्ता और शक्ति को बढ़ाते हैं। लौकी, कढ़ू के गुण के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह प्राणों को अपने अंदर सोखते हैं और साथ ही प्राणों का प्रसार भी करते हैं। यह इस धरती पर सबसे अधिक प्राणवान और ऊर्जा प्रदान करने वाली शाक, सब्जी है। जिस प्रकार अश्वथ का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है उसी प्रकार लौकी, कढ़ू ऊर्जा को ग्रहण या अवशोषित कर उसका प्रसार करते हैं।सम्पूर्ण सृष्टि – प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष , अभिव्यक्त व अनभिव्यक्त – एक बड़ी गेंद , गोलाकार कढ़ू के समान है। इसमें हर प्रकार की विविधता पाई जाती है – छोटे से बड़े तक। ‘कू’ का अर्थ है छोटा, ‘ष्’ का अर्थ है ऊर्जा और ‘अंडा’ का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला – सृष्टि या ऊर्जा का छोटे से वृहद ब्रह्मांडीय गोला। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में ऊर्जा का संचार छोटे से बड़े में होता है। यह बड़े से छोटा होता है और छोटे से बड़ा; यह बीज से बढ़ कर फल बनता है और फिर फल से दोबारा बीज हो जाता है। इसी प्रकार, ऊर्जा या चेतना में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने का और विशाल से विशालतम होने का विशेष गुण है, जिसकी व्याख्या देवी कूष्मांडा करती हैं। इसका अर्थ यह भी है कि देवी माँ हमारे अंदर प्राणशक्ति के रूप में प्रकट रहती हैं। कुछ क्षणों के लिए बैठकर अपने आप को एक कढ़ू के समान अनुभव करें। इसका यहाँ पर यह तात्पर्य है कि अपने आप को उन्नत करें और अपनी प्रज्ञा, बुद्धि को सर्वोच्च बुद्धिमत्ता जो देवी माँ का रूप है, उसमें समा जाएँ। एक कढ़ू के समान आप भी अपने जीवन में प्रचुरता, बहुतायत और पूर्णता अनुभव करें। साथ ही सम्पूर्ण जगत के हर कण में ऊर्जा और प्राणशक्ति का अनुभव करें। इस सर्वव्यापी, जागृत, प्रत्यक्ष बुद्धिमत्ता का सृष्टि में अनुभव करना ही कूष्माण्डा है।

डाटा, ज्ञान और नवाचार ही असली ताकत: पीएम मोदी बोले- अहम यह है कि इनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डाटा, ज्ञान, तकनीक और नवाचार की असली ताकत इस बात में है कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में व्यापार, ऊर्जा, खनिज और तकनीक का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए हो रहा है, जबकि भारत का जोर लोगों को सशक्त बनाने पर है। डिजिटल भुगतान, लाभार्थियों के खातों में सीधे सरकारी सहायता और कोविन जैसे मंचों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत अपनी डिजिटल क्षमताओं को दूसरे देशों के साथ साझा कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि 21वीं सदी में डाटा, ज्ञान और नवाचार ताकत के नए स्रोत बन गए हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि ताकत किसके पास है, बल्कि यह है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को लेकर साझा किए गए अपने संदेश में कही। पीएम मोदी ने कहा कि तकनीक कुछ लोगों को आगे बढ़ाने का जरिया बनेगी या इससे लाखों लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे, यह अहम सवाल है। इस बार यह फोरम पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा



कि पावर टू एम्पावर (सशक्त बनाने की ताकत) की यह मानवीय भावना सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं है। यह हमें हजारों वर्षों की परंपरा ने सिखाया है। भारत में हमने इसे अपनी गवर्नेंस और अपनी कार्य-संस्कृति में लागू करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्ञान, धन और शक्ति रखने वाले किसी भी व्यक्ति का आकलन इस बात से होना चाहिए कि वह उनका इस्तेमाल कैसे करता है। उन्होंने कहा कि भारत में यह विचार नया नहीं है। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने समझाया कि ज्ञान का इस्तेमाल विवाद, धन का इस्तेमाल घमंड और शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। इसके बजाय ज्ञान का उपयोग समझ बढ़ाने, धन का इस्तेमाल दान और शक्ति

का इस्तेमाल दूसरों की रक्षा के लिए होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि असली सवाल यह है कि क्या ज्ञान कुछ लोगों की ताकत बनकर रह जाएगा या इससे सभी की क्षमताएं बढ़ेंगी। यहीं से एक नई सोच पैदा होती है, जिसे उन्होंने ‘पावर टू एम्पावर’ यानी दूसरों को सशक्त बनाने की ताकत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘पावर टू एम्पावर’ का मतलब दूसरों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें सक्षम बनाना, प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग करना और सिर्फ अपनी सफलता के बजाय दूसरों को सफल होने में मदद करना है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ वह यहां आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। देश में 100 से अधिक भाषाएं, करीब 80 हजार पंजीकृत समाचार पत्र और प्रकाशन तथा एक हजार से

अधिक सैटेलाइट टीवी चैनल हैं। सोशल मीडिया के दौर में भारत में 50 करोड़ से अधिक यूट्यूब उपयोगकर्ता और 50 करोड़ से ज्यादा इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि देश में अलग-अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है और लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। इसमें डिजिटल ताकत ने बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश से आए मेहमानों से भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था का अनुभव करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत में रेहड़ी लगाने वाला और कार शोरूम चलाने वाला कारोबारी अलग-अलग स्तर पर काम करते हैं, लेकिन दोनों डिजिटल भुगतान के लिए एक ही मंच का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इसे समावेशी तकनीक की ताकत बताया।

बरेली में सीएम योगी बोले: पहले जो रहनुमा थे, वही चोर थे, अब यूपी सुरक्षित;ग्राम प्रहरियों को दी बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली से प्रदेश के 68 हजार ग्राम प्रहरियों को बड़ी सौगात दी। उनके मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रहरियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली में ग्राम प्रहरियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम प्रहरियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। अब उनका मानदेय 3500 रुपये होगा, जो पहले 2500 रुपये था। इसके साथ ही, उन्हें प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक की कैशलेस उपचार सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले यहां त्योहारों पर उपद्रव होते थे। अब लोग सुरक्षित माहौल में पर्व मना रहे हैं। प्रदेश के हर गांव में हजारों लोग शारदीय नवरात्र से जुड़े हैं। लोग निडर होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। वे सुरक्षित माहौल में देवी मां के दर्शन कर पा रहे हैं।



सीएम ने कहा कि सुरक्षित उत्तर प्रदेश बनने से देश और दुनिया में प्रदेश की धारणा बदली है। पहले चंद मुट्ठी भर लोगों की गलतियों का खामियाजा 25 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ता था। नौजवानों और व्यापारियों के सामने पहचान का संकट आता था। अब यूपी के बारे में कोई सवाल नहीं उठता। दूसरे राज्य यूपी जैसा बनना चाहते हैं। सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन का नया दौर योगी ने सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन को वर्तमान माहौल का आधार बताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के इस माहौल से सभी को लाभ मिला है। सड़कें बन रही हैं और निवेश आ रहा है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। लोगों में विश्वास है कि वे सुरक्षित हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक

सकता। पहले जो रहनुमा थे, वही चोर थे- सीएम - मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले जो सत्ता में थे, वही लूट-खसोट करते थे। डकैती डलवाते थे। जो रहनुमा थे, वही चोर थे। आज अपराधियों में कानून का डर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई बेटियों से गुस्ताखी करता है, तो उसका अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है और उत्सव का माहौल है। यह माहौल लोगों के विश्वास के कारण है कि वे सुरक्षित हैं। यह सब टीम वर्क से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, तो इन सुविधाओं का लाभ होमगार्ड, पीआरडी और ग्राम प्रहरियों को भी मिलना चाहिए। ग्राम प्रहरी अपने गांव में रहकर

सूचना एकत्र करें और अपने थानाध्यक्ष या दरोगा को उपलब्ध करा दें। गांव में ग्राम प्रहरियों की भूमिका सीसीटीवी की तरह है। करीब 11-20 बजे पुलिस लाइन मैदान पर हेलिकॉप्टर से पहुंचें। जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के मंच पर अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी राजीव कृष्ण भी मौजूद थे। ग्राम प्रहरियों के योगदान पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रहरियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंच पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर, वन मंत्री अरुण कुमार, कैबिनेट मंत्री एवं राज्यसभा सांसद धर्मपाल सिंह, सांसद छत्रपाल गंगवार, राज्यसभा सांसद श्रुति गंगवार और मेयर उमेश गौतम आदि उपस्थित थे। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सुरक्षा में ग्राम प्रहरियों के योगदान की सराहना की। कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा सांसद धर्मपाल सिंह ने क्षेत्रीय बोली में कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने पीडीए को लेकर सपा पर निशाना साधा। धर्मपाल सिंह ने भाजपा की आगामी जीत का दावा भी किया।

अखिलेश यादव बोले: चुनाव आयोग सामने आए, कहे भाजपा के इशारे पर नहीं करेगा काम:नौकरशाही भी सुधरे

अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ की सदर विधानसभा में एक ही व्यक्ति के दस वोट बन गए हैं। चुनाव आयोग सामने आए और कहे कि वह भाजपा के इशारे पर काम नहीं करेगा। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग और नौकरशाही भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से चला रही है। लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। भाजपा सत्ता से हटेगी, तभी यह संकट हटेगा। अखिलेश ने डॉ. राममनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर लोहिया पार्क में श्रद्धांजलि देने के बाद ये बातें पत्रकारों से कहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव अयोग का रवैया और कार्य भेदभावपूर्ण है। अब दोबारा से वोट बनाने का अभियान चल रहा है, जिस एसआईआर प्रक्रिया में करोड़ों रुपये खर्च हुए, प्रचार हुआ और पूरा प्रशासन लगा, अब उसे शून्य कर दिया गया। एसआईआर में किसी का फर्जी वोट नहीं बनना चाहिए था, लेकिन मतदाता सूची में लाखों वोट फर्जी बन गए हैं। उन्होंने



कहा कि आजमगढ़ की सदर विधानसभा में एक ही व्यक्ति के दस वोट बन गए हैं। चुनाव आयोग सामने आए और कहे कि वह भाजपा के इशारे पर काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता और सपा कार्यकर्ता भाजपा की चार सौ बीसी नहीं चलने देंगे। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से हर बूथ पर दो-दो सौ वोट बढ़ाने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्देश इसलिए दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव आयोग भाजपा और सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। भाजपा चाहती है जो उसके सदस्य है, मतदाता सूची में सिर्फ उन्हीं का नाम

रहे। केवल भाजपा के सदस्य ही देश के नागरिक रहें। हम सब जानते हैं कि जिसका वोट नहीं, वह देश का नागरिक नहीं रहेगा। आजमगढ़ की सदर विधानसभा में विकास यादव नाम के दस वोट हैं, एक वोट विकास यादव डालेगा और बाकी नौ वोट भाजपा के लोग डाल देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों के साथ अमानवीय और बर्बरतापूर्ण करवाई कर रही है। महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। भाजपा ने हिटलर की तर्ज पर प्राइवेट फोर्स बना रखी है। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी व श्याम लाल पाल प्रदेश भी उपस्थित रहे।

त्योहारी सीजन में दुकानदारों को बड़ी राहत: दिवाली तक नहीं लगेगा यूपीआई पर चार्ज

यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लागू करने की समयसीमा को सरकार ने बढ़ा दी है। 15 अक्टूबर की जगह अब यह चार्ज दिवाली के बाद लागू होगा। हालांकि यह किस तारीख से लागू होगा अभी इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। यूपीआई से भुगतान करने वालों और दुकानदारों के लिए अहम खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने का फैसला दिवाली

के बाद तक टाल दिया है। एनपीसीआई ने मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान में बताया कि यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। अब यह शुल्क दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा, हालांकि इसकी सटीक तारीख अलग से घोषित होगी। यह शुल्क सभी यूपीआई भुगतानों पर नहीं लगेगा, बल्कि तय शर्तों के तहत आने वाले कुछ कारोबारी लेनदेन पर ही लागू

होगा। मर्चेंट डिस्काउंट रेट यह शुल्क है, जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले दुकानदार या कारोबारी को बैंक और पेमेंट प्रोसेसर को देना पड़ता है। इस शुल्क का इस्तेमाल भुगतान व्यवस्था से जुड़े अलग-अलग भागीदारों की लागत को पूरा करने और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चलाने में किया जाता है। सरकार और NPCI ने स्पष्ट किया है कि MDR U तो कोई टैक्स है और न ही सरकार या NPCI की ओर से वसूला जाने वाला शुल्क।

झोला उठाने का वक्त आ गया: महंगाई के आंकड़ों को लेकर सरकार पर हमलवार कांग्रेस

जयराम रमेश ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गरीब की थाली से निवाला, मध्यम वर्ग की जेब से बचत गायब हो रही है और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अहंकार में डूबे हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बढ़ती महंगाई को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि लगभग हर खाद्य पदार्थ की कीमतें %सभी सीमाएं पार कर चुकी हैं%। वोटों की चोरी सच्चाई है। कमर तोड़ महंगाई हकीकत है। कांग्रेस नेता ने अपने एक्स हैंडल पर एक मीडिया रिपोर्ट शेयर किया और



कहा कि सितंबर महीने में महंगाई 5.54 प्रतिशत पहुंच गई है, लेकिन असली बात यह है कि खाद्य महंगाई 7.74 प्रतिशत हो गई है यानी खाने की लगभग हर चीज की कीमत हद पार कर चुकी है। जैसे प्याज 108 प्रतिशत महंगा, लहसुन 55 प्रतिशत, अदरक 63 प्रतिशत और नींबू 36 प्रतिशत महंगा हो गया है। जयराम रमेश ने कहा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई मार्च के 3.40

प्रतिशत से लगातार बढ़ते हुए सितंबर में 5.54 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो 23 महीने का उच्चतम स्तर है। महंगाई का असर सिर्फ थाली तक सीमित नहीं है। परिवहन, शिक्षा, कपड़े-जूते और घरेलू सामान सहित सब जरूरी सामान महंगे हो रहे हैं। गरीब की थाली से निवाला, मध्यम वर्ग की जेब से बचत गायब हो रही है और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अहंकार में डूबे हैं, जनता की परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रहे। अच्छे दिन का वादा करके सत्ता में आने वाली सरकार वोट चोरी के साथ साथ बचत चोरी भी कर रही है।

संपादकीय

Editorial

Neither suspension nor stay

The Supreme Court rejected the demand for the suspension of Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar Gupta and did not even impose an interim stay on his work and decision-making. However, it did warn that if the Election Commission's internal decisions, including the Special Intensive Review (SIR) or other significant changes, are not made unanimously, the Supreme Court may overturn them. This is a very harsh warning from the Supreme Court regarding the functioning and internal discrepancies of a constitutional institution. Another Supreme Court judge, Justice Ujjwal Bhuyan, considered the disenfranchisement of millions of people an attack on the "spirit of the Constitution." The Constitution does not permit two classes of citizens. No citizen who has been a voter can be deprived of their right to vote without notice and before a final decision. We do not want such an Election Commission. Former Supreme Court judge Justice Nariman has raised the question: why did the Supreme Court remain a mute spectator when the names of millions of voters were deleted from voter lists, and this process is still ongoing? While this exercise continues in the name of the Constitution and its articles, why hasn't the Supreme Court issued a firm verdict? This means that the roles of the Election Commission, the Special Election Inspector (SIR), and the Central Election Commission (CEC), and the protests surrounding them, have taken on new dimensions. Until now, the political opposition considered the Election Commission and the alleged purification of voter lists as "vote theft" and has been constantly agitated. However, following the objections of two Election Commissioners, current and former Supreme Court judges have also issued sharp comments, making the issue extremely serious and a matter of constitutional justification.

The controversy is spreading rapidly. The most significant judicial observation was that, regarding the "technical changes" to Form 6, which the Election Commission had been clarifying had been deemed "appropriate" by the Supreme Court, Chief Justice Surya Kant categorically stated that the Supreme Court had not approved any "technical changes." So, was the Election Commission telling a "blatant lie" to the nation? Does this not amount to contempt of court? Nevertheless, the Supreme Court has issued notices not only to CEC Gyanesh Kumar, but also to both Election Commissioners—Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi—as well as relevant officials of the Commission and the Central Government. Chief Justice Surya Kant clearly stated that no decisive action can be taken based on media reports and news reports. Therefore, the court has summoned the minutes of the Commissioners' meetings, agendas, minutes, documents, Form 6, and the accompanying documents used to decide on the manifesto. The Supreme Court's judicial bench will examine all the records and attempt to reach a conclusion as to whether the Commission's decisions have been unilateral or unanimous.

Since this issue has now reached such depth and scope, the Supreme Court must also review the 2023 law that grants the CEC unprecedented legal protection even after retirement. Such protection is not granted even to the Prime Minister of the country. Only the President is granted this legal immunity. Has the CEC now become equivalent to the President? The Supreme Court will undoubtedly review the validity of this immunity. Now that the Supreme Court has directly intervened in Election Commission-related disputes, the opposition should tone down its agitation. On Tuesday, MPs from 19 constituent parties of the "Indi" alliance had planned a protest march from Parliament House.

Is the world prepared for these changes?: The threat of a major weather disaster in 2027

In March, a massive wave that emerged from beneath the Pacific Ocean surface has created Super El Niño-like conditions across the world, including India. These are not imaginary fears; they are concrete predictions, supported by climate models worldwide. In March, satellite sensors began detecting a massive wave moving eastward along the equator beneath the Pacific Ocean surface. As this wave moved toward the coast of South America, it increased ocean height and temperature and warmed and moistened the air above. This triggered powerful storms, leading to widespread changes in the atmosphere. These waves soon spread across the globe, altering temperatures, rainfall, and the movement of storm systems. The El Niño wave generated by that massive wave has since warmed a portion of the central and eastern equatorial Pacific Ocean by more than three degrees Celsius above its average temperature. Estimates indicate that there's a greater than 80 percent chance that this El Niño (a natural climate phenomenon that occurs every few years) will remain very strong for the rest of the year and could become the most powerful El Niño ever recorded. More than two dozen climate models from agencies around the world predict El Niño conditions, and they often disagree. However, this year, they are more unanimous than ever that El Niño conditions will persist until the end of 2026. This greater certainty means that the predicted impacts (such as heavy rainfall in some areas, drought and wildfires in others, as well as increased global temperatures) are more likely to occur. This also means that governments, businesses, and communities can take advantage of this exceptionally clear scientific insight. Therefore, there's still time to prepare. Previous El Niño events give us an idea of ??many of the potential impacts. Decreased rainfall and drought are expected in Southern Africa and India, which could impact food supplies and disrupt hydroelectric power generation. Drought in Indonesia has already triggered forest fires and is expected to continue. Summers in the Southern Hemisphere during winter could be very hot, with heatwaves likely in parts of Australia and Brazil. Other regions, such as Kenya, eastern China, and South America, are expected to experience above-average rainfall. Current projections indicate that parts of the southeastern United States have a greater than 70 percent chance of experiencing above-normal rainfall between October and December, which could increase the risk of floods and landslides. El Niño events are also associated with sudden increases in Earth's surface temperature. Oceans cover 70 percent of the Earth's surface, so oceans absorb a significant portion of the energy trapped by greenhouse gases, resulting in warming. El Niño events help release some of that energy back into the atmosphere. The last three major El Niño events, in 1997, 2015, and 2023, saw significant increases in surface temperatures. Each year was the hottest year on record, and temperatures persisted in subsequent years. In fact, the temperatures of each subsequent year (1998, 2016, and 2024) exceeded previous record-breaking temperatures. Rising temperatures could worsen weather patterns. Heat waves could increase, droughts and wildfires could become more frequent, and storms could bring heavier and more frequent rainfall. This will impact the entire world, potentially leading to even more severe weather in 2027. The changes caused by the so-called "Super El Niño" will adversely impact agriculture, energy and water security, ecosystems, supply chains, finance, travel, and health. Governments, communities, and businesses should assess their ability to cope with such disruptions and prepare the necessary resources and plans to deal with them. We can assume that the summer of 2027 will be extremely hot in the Northern Hemisphere. Given this, healthcare systems and hospitals should be prepared to deal with an increased number of patients suffering from heatstroke, heart, and kidney problems. Municipalities should review their methods for dealing with extreme heat. This should include care systems for the elderly and sick, community cooling center plans, and rules for warning people when venturing outside is risky. They should also develop plans for managing power supplies. The risk of wildfires may increase significantly in many parts of the world. In this context, steps can be taken, such as better coordination between various agencies, increased funding for firefighting teams, and improved warning systems for people living in vulnerable areas. States and governments can also encourage homeowners to protect their property; such as clearing bushes or installing fire-resistant roofs. Supply chains could be disrupted, leading to problems like hoarding, profiteering, and market instability. The United Nations World Food Programme has already released funds to some areas of Africa, anticipating crop losses. California has also increased its exports due to the potential for flooding associated with El Niño. We have already deployed equipment like sandbags and pumps to deal with flooding along rivers and coasts. These El Niño projections aren't mere hypotheticals about future heat. They are concrete predictions about climate and weather conditions, some of which could be quite disruptive over the next 18 months. There's still time to prepare, plan, and strengthen our systems.

Opposition on the Streets: How many genuine issues does the Congress have? Why is the Election Commission under attack?

The opposition's core objections to the SIR reached the Supreme Court. Questions were raised about the Election Commission's authority, voter list revision, and document and citizenship verification, but the court did not order a stay on the SIR. In a democracy, the opposition's role is to question the government, expose the shortcomings of its policies, and strongly raise public issues. However, the opposition's continued targeting of the Election Commission and Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar over the Special Intensive Revision (SIR) raises the question: does the opposition lack more important public issues to corner the government? As the saying goes, "A disgruntled cat scratches the pole." After repeated political defeats, there are many who view the opposition's strategy through this very prism. Although the public decides the intentions of a political party in a democracy, the choice of issues certainly reflects the issues on which a party wishes to hold the government accountable. The opposition's core objections to the SIR reached the Supreme Court. Questions were raised regarding the Election Commission's authority, voter list revision, and verification of documents and citizenship, but the court did not order a stay on the SIR. On July 10, 2025, the Supreme Court did not stay the SIR in Bihar. Instead, it asked that documents such as Aadhaar cards, water cards, and ration cards be considered for greater inclusiveness in the process. On July 28, 2025, the court also refused to stay the publication of the draft voter list. That is, instead of immediately halting the process that had generated so much political uproar, the court allowed it to proceed while safeguarding the law and voter rights. Subsequently, on August 22, 2025, the court directed the disclosure of information related to approximately 6.5 million voters whose names were not on the draft list and provided them with an opportunity to file claims. Booth-level agents of political parties were also instructed to assist the public. Clearly, the court's objective was not to halt the SIR, but to ensure that no eligible voter was deprived of the opportunity to express their views. Then came the landmark judgment of May 27, 2026. The Supreme Court upheld the validity of the SIR conducted by the Election Commission in Bihar and dismissed the petitions challenging it. The court held that the Election Commission has the power to conduct a Special Intensive Revision under Article 324 of the Constitution and Section 21(3) of the Representation of the People Act. The court also acknowledged that the accuracy of voter lists is essential for free and fair elections, and that the Election Commission can conduct limited citizenship verification to determine voter eligibility. This means that the Supreme Court has accepted the fundamental right to the very process that was being questioned. In such a situation, it's natural to ask: has this become a "mountain-and-a-moon scenario"? First, the attempt to declare the SIR unconstitutional, then the Supreme Court hearing, and finally the court's upholding of its fundamental legality, have led those who consider this an uncomfortable situation for the opposition to be using similar rhetoric in political discourse. The Question of Illegal Migration and the Politics of Appeasement An important aspect of the entire SIR debate is the possibility of illegal migration and ineligible people being included in the voter list. The issue of cross-border illegal migration in states like Bihar and West Bengal has long been a topic of political debate, but also a concern for Indian demography. These infiltrators have been implicated in numerous riots, violence, and terrorist activities in the country. If there is a suspicion of foreign nationals being illegally included in the voter list in a state, it should be the natural responsibility of the electoral system to investigate. One thing should be absolutely clear here: it is wrong to label someone an infiltrator simply because they are Muslim. Citizenship is not determined by religion.

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत मुरादाबाद में 14 से 16 अक्टूबर तक लगेंगे जागरूकता एवं आवेदन सहायता शिविर

जिलाधिकारी श्री अनुनय झा ने उपायुक्त उद्योग सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की, समयबद्ध एवं प्रभावी आयोजन के लिए निर्देश जनपद के आठ विकास खंडों, नगर निगम तथा विभिन्न नगर निकायों में आयोजित होंगे शिविर, युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना के लिए किया जाएगा जागरूक उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, नए उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद मुरादाबाद में विशेष जागरूकता एवं आवेदन सहायता शिविर आयोजित किए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14, 15 एवं 16 अक्टूबर 2026 को जनपद के विभिन्न विकास खंडों, नगर निगम तथा नगर निकायों में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से पात्र युवक-युवतियों को योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक अभिलेखों तथा उद्यम स्थापना की प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा। शिविरों के आयोजन एवं तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी श्री अनुनय झा ने उपायुक्त उद्योग श्री दीपेंद्र कुमार सहित संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शिविरों के आयोजन, अधिकारियों की जिम्मेदारियों, युवाओं तक योजना की जानकारी पहुंचाने तथा आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्धारित तिथियों पर सभी शिविरों का आयोजन सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित किया जाए। संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करें। अधिक से अधिक पात्र युवाओं को शिविरों में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि उन्हें योजना के लाभों की जानकारी मिल सके और वे स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार तलाशने वाले के साथ-साथ रोजगार सृजित करने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान महत्वपूर्ण पहल है। योजना का लाभ पात्र युवाओं तक पहुंचाने के लिए विभागीय



अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इच्छुक युवाओं को आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा न हो तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाए। युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना का अवसर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को अपना व्यवसाय अथवा उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के अंतर्गत विनिर्माण, सेवा क्षेत्र तथा अन्य पात्र व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। इसके माध्यम से युवा अपनी योग्यता, कौशल एवं रुचि के अनुरूप उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए ब्याजमुक्त ऋण एवं बिना गारंटी ऋण सुविधा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की व्यवस्था है। योजना का व्यापक उद्देश्य प्रदेश में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। योजना के तहत प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के लिए पात्रता-मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास अथवा समकक्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से कौशल संबंधी प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री की निर्धारित शर्त पूरी करना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को अपने

प्रस्तावित उद्यम से संबंधित परियोजना रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक अभिलेख तैयार रखने चाहिए। आवेदन के समय योजना की प्रचलित पात्रता शर्तों एवं विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन एवं आवश्यक अभिलेख इच्छुक पात्र युवा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के आधिकारिक पोर्टल [nysa.up.gov.in](#) पर ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति, पासपोर्ट आकार का फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक प्रमाणपत्र, आयु एवं निवास संबंधी प्रमाणपत्र, कौशल अथवा प्रशिक्षण प्रमाणपत्र तथा प्रस्तावित उद्यम की परियोजना रिपोर्ट सहित आवश्यक अभिलेख तैयार रखने होंगे। जाति प्रमाणपत्र भी संबंधित श्रेणी में लागू होने पर प्रस्तुत करना होगा। शिविरों में युवाओं को आवेदन प्रक्रिया, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विकास खंडवार शिविर कार्यक्रम-ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी शिविर प्रातः 10 बजे आयोजित होंगे। 14 अक्टूबर 2026, बुधवार विकास खंड मूँढापांडे- नोडल अधिकारी श्री योगेश कामेश्वर, सहायक आयुक्त उद्योग, सहयोगी श्री मधुर गुप्ता। विकास खंड कुंदरकी- नोडल अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार, सहायक आयुक्त उद्योग सहयोगी, श्री हर्ष सैनी। विकास खंड मुरादाबाद- नोडल अधिकारी श्री मो. आजम, सहायक आयुक्त उद्योग, सहयोगी श्री निपेन्द्र कुमार। विकास खंड छजलैट-नोडल अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह, सहायक आयुक्त उद्योग, सहयोगी श्री गजेन्द्र। विकास खंड बिलारी- नोडल अधिकारी श्री अमित कुमार,

अपर सांख्यिकीय अधिकारी, सहयोगी श्री इरफान। विकास खंड भगतपुर टांडा- नोडल अधिकारी श्री अभिषेक वर्मा, अपर सांख्यिकीय अधिकारी सहयोगी श्री जय प्रकाश। 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार विकास खंड ठाकुरद्वारा- नोडल अधिकारी श्री जोगेन्द्र सिंह, सहायक आयुक्त उद्योग, सहयोगी श्री गजेन्द्र। विकास खंड डिलारी- नोडल अधिकारी श्री अमित कुमार, अपर सांख्यिकीय अधिकारी सहयोगी श्री इरफान। नगरीय निकायों में शिविर कार्यक्रम- नगरीय क्षेत्रों में भी शिविर प्रातः 10 बजे आयोजित किए जाएंगे, ताकि शहरी क्षेत्र के पात्र युवाओं को योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक किया जा सके। 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार नगर पंचायत अगवानपुर - नोडल अधिकारी श्री योगेश कामेश्वर, सहायक आयुक्त उद्योग, सहयोगी श्री मधुर गुप्ता। नगर पंचायत उमरी कला- नोडल अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार, सहायक आयुक्त उद्योग, सहयोगी श्री हर्ष सैनी। नगर पंचायत महमूदपुर माफी- नोडल अधिकारी श्री मो. आजम, सहायक आयुक्त उद्योग, सहयोगी श्री निपेन्द्र कुमार। नगर पालिका परिषद बिलारी - नोडल अधिकारी श्री अभिशोक वर्मा, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, सहयोगी श्री जय प्रकाश। 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार पंचायत भवन मुरादाबाद- नोडल अधिकारी श्री मो. आजम, सहायक आयुक्त उद्योग, सहयोगी श्री मधुर गुप्ता। पंचायत भोजपुर धर्मपुर- नोडल अधिकारी श्री योगेश कामेश्वर, सहायक आयुक्त उद्योग, सहयोगी श्री निपेन्द्र कुमार। नगर पालिका परिषद ठाकुरद्वारा- नोडल अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार, सहायक आयुक्त उद्योग, सहयोगी श्री हर्ष सैनी। नगर पंचायत कुंदरकी- नोडल अधिकारी श्री जोगेन्द्र सिंह, सहायक आयुक्त उद्योग, सहयोगी श्री गजेन्द्र। नगर

पंचायत ढकिया- नोडल अधिकारी श्री अमित कुमार, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, सहयोगी श्री इरफान। नगर पंचायत पाकबड़ा- नोडल अधिकारी श्री अभिषेक वर्मा, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, सहयोगी श्री जय प्रकाश। पात्र युवा शिविरों में पहुंचकर प्राप्त करें जानकारी-जिला प्रशासन की ओर से युवाओं से अपील की जाती है कि वे अपने क्षेत्र में निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार आयोजित शिविरों में प्रतिभाग कर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जानकारी प्राप्त करें। जो युवा अपना व्यवसाय या उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, वे आवश्यक अभिलेखों के साथ शिविर में पहुंचकर आवेदन प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी श्री अनुनय झा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों के आयोजन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा योजना का लाभ अधिकाधिक पात्र युवाओं तक पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत पीएमएस पब्लिक स्कूल में डाक टिकट प्रदर्शनी आयोजित। एडीएम सिटी श्री अंकुर श्रीवास्तव ने किया उद्घाटन, विद्यार्थियों को डाक टिकट संग्रह एवं डाक सेवाओं के महत्व को लेकर दो गई जानकारी। राष्ट्रीय डाक सप्ताह (9 से 15 अक्टूबर) के अंतर्गत डाक विभाग, मुरादाबाद द्वारा जन-जागरूकता एवं डाक सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सोमवार को फिलाटेली दिवस (डाक टिकट संग्रह दिवस) के अवसर पर पीएमएस पब्लिक स्कूल, मुरादाबाद में दुर्लभ एवं प्राचीन डाक टिकटों तथा प्रथम दिवस आवरणों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन अपर जिलाधिकारी (नगर) श्री अंकुर श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में प्रदर्शित दुर्लभ एवं ऐतिहासिक डाक टिकटों का

अवलोकन करते हुए अपर जिलाधिकारी (नगर) श्री अंकुर श्रीवास्तव ने कहा कि डाक टिकट संग्रह केवल एक शौक नहीं, बल्कि देश के इतिहास, संस्कृति, कला और भौगोलिक विरासत को जानने का महत्वपूर्ण माध्यम है। डाक टिकटों के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, महान व्यक्तित्वों तथा देश की सांस्कृतिक विविधता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में ज्ञानार्जन, रचनात्मकता और ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति रुचि विकसित करने में सहायक हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्या निश्मा ने विद्यार्थियों को पत्र-लेखन के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि पत्र-लेखन संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। उन्होंने डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं की जानकारी देते हुए पार्सल, स्पीड पोस्ट, डाक जीवन बीमा (पीएलआई/आरपीएलआई), सुकन्या समृद्धि योजना तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की सेवाओं के बारे में बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को डाक विभाग की सेवाओं एवं बचत योजनाओं के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान 'स्वच्छता ही सेवा-2026' अभियान के अंतर्गत 'एकजुट प्रयास, प्रभावी बदलाव' संदेश के साथ स्थापित सेल्फी प्वाइंट पर अपर जिलाधिकारी (नगर) श्री अंकुर श्रीवास्तव ने सेल्फी लेकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने प्रदर्शनी का उत्साहपूर्वक अवलोकन किया तथा डाक टिकटों से जुड़ी ऐतिहासिक एवं रोचक जानकारियां प्राप्त कीं। डाक विभाग की ओर से आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को उपहार एवं पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के साथ-साथ डाक विभाग की गतिविधियों एवं सेवाओं के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने का प्रयास किया गया। यह कार्यक्रम प्रवर अधीक्षक डाकघर, मुरादाबाद मंडल के मार्गदर्शन में उप डाकघर (सिटी), मुरादाबाद द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक मैथ्यू सहित विद्यालय का स्टाफ तथा डाक विभाग से श्री अरुण मोहन सांख्यधर, श्री आशुतोष शर्मा, श्री आयुष यज्ञसेनी, श्री शिवम सक्सेना सहित अन्य संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

अवैध अस्पतालों एवं क्लीनिकों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

जनपद में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों एवं क्लीनिकों के विरुद्ध जिलाधिकारी श्री अनुनय झा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक अभियान चलाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कुलदीप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 05 चिकित्सकीय टीमों का गठन कर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सघन निरीक्षण एवं छापेमारी की गई। अभियान के दौरान 12 अस्पतालों एवं क्लीनिकों के

विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें कई अवैध प्रतिष्ठानों को मौके पर सील किया गया तथा संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास कुमार सिंह द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान उमरी कला चैराहा स्थित तोतन कुमार महाजन क्लीनिक अवैध रूप से संचालित पाया गया, जिसे मौके पर सील कर दिया गया। इसी प्रकार छजलैट तिराहा स्थित सैफी डेंटल केयर

सेंटर के विरुद्ध भी सील करने की कार्रवाई की गई। कांठ रोड, भीकनपुर स्थित एम.एस. पैथोलॉजी लैब तथा उमरी चैराहा स्थित मेरठ हेल्थ केयर सेंटर भी अवैध रूप से संचालित पाए गए, जिनके विरुद्ध सील करने की कार्रवाई की गई। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. शर्मा द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान कांठ स्थित न्यू केजीएन हॉस्पिटल में मानकों का सत्यापन किया गया। निरीक्षण में ऑपरेशन थिएटर

(ओटी) संचालन के निर्धारित मानक पूर्ण नहीं पाए गए। इस पर ओटी को सील करते हुए अस्पताल संचालक को नोटिस जारी किया गया। वहीं कांठ के ग्राम मुख्तयारपुर नवादा स्थित अमजद क्लीनिक भी अवैध रूप से संचालित पाया गया, जिसे मौके पर सील करते हुए संचालक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सौरभ सिंह के नेतृत्व में मुंडापांडे के ग्राम वीरपुर स्थित सिटी हेल्थ

केयर का निरीक्षण किया गया। मौके पर पंजीकृत चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं पाया गया, जिसके दृष्टिगत अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में गत्ता फैक्ट्री, अक्का डिलारी, मुंडापांडे स्थित ए. अब्दुल रहमान द्वारा संचालित क्लीनिक भी अवैध रूप से संचालित पाया गया, जिसे सील कर दिया गया। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव द्वारा सुरजनपुर,

ठाकुरद्वारा स्थित चैधरी क्लीनिक का निरीक्षण किया गया, जहां क्लीनिक का संचालन अवैध रूप से होता पाया गया। इसके विरुद्ध सील करने की कार्रवाई की गई। वहीं सुरजनपुर स्थित शिफा क्लीनिक के अभिलेखों की जांच में क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण की अवधि समाप्त पाई गई। साथ ही क्लीनिक संचालन के निर्धारित मानक भी पूर्ण नहीं पाए गए।

संक्षिप्त समाचार

पोषण स्तर में सुधार और आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए जिले में चलेगी विशेष पहल

स्थानांतरित होने के बावजूद नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले तीन सीडीपीओ के अक्टूबर माह के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश। जिलाधिकारी श्री अनुनय झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पोषण समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, पोषण संबंधी योजनाओं की प्रगति, पोषण पुनर्वास केंद्रों की कार्यप्रणाली तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोषण कार्यक्रमों का प्रभावी क्रिया-व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को योजनाओं का लाभ समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराया जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण सुधार के लिए लागू होगा अभिनव प्रयोग- जिलाधिकारी ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने और उनके पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से जनपद के प्रत्येक विकास खंड के 10 चिन्हित आंगनवाड़ी केंद्रों पर विशेष नवाचार शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासनिक स्तर से इस योजना के अंतर्गत 15 नवंबर से 15 मार्च तक बच्चों को सप्ताह में दो बार चना, तिल और गुड़ से तैयार पौष्टिक 'सुपर लड्डू' उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सप्ताह में एक बार दूध तथा दो बार मौसमी फल दिए जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। बच्चों को पौष्टिक आहार के प्रति आकर्षित करने के लिए रोस्टेड नमकीन और गुड़ की चिक्की जैसे खाद्य पदार्थों को भी पहल में शामिल किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, वितरण की नियमितता और बच्चों को मिलने वाले पोषण लाभ पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस पहल की निगरानी के लिए संबंधित सुपरवाइजर्स को चयनित केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि योजना का प्रभावी क्रिया-व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। 15 मार्च के बाद गर्मियों के मौसम में बच्चों को सत्तू सहित अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए 'स्टार ऑफ द मंथ' पहल पर जोर- जिलाधिकारी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना पोषण कार्यक्रमों की सफलता के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य से बच्चों और उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। बैठक में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए आकर्षक गतिविधियों के साथ-साथ माह में सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले बच्चे को 'स्टार ऑफ द मंथ' के रूप में सम्मानित करने की पहल पर जोर दिया गया। इससे बच्चों में केंद्र आने के प्रति रुचि बढ़ाने तथा अभिभावकों को नियमित रूप से बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र भेजने के लिए प्रेरित करने में सहायता मिलेगी। पोषण वाटिकाओं को विकसित कराने के निर्देश- जिलाधिकारी ने प्रत्येक विकासखंड के 10 आंगनवाड़ी केंद्रों पर बेहतर पोषण वाटिकाएं विकसित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोषण वाटिकाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। संबंधित अधिकारी केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं, स्वच्छता और पोषण गतिविधियों की नियमित निगरानी करें तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। स्थानांतरित तीन सीडीपीओ के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए कि जब तक संबंधित अधिकारी अपनी नवीन तैनाती वाली परियोजना में कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक अक्टूबर माह का वेतन आहरित न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा। पोषण पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के निर्देश- जिलाधिकारी ने ठाकुरद्वारा और बिलारी में 10-10 बेड की क्षमता वाले पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के लिए शासन स्तर पर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक पत्राचार करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों को समय पर उचित उपचार और पोषण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जाएं। इसके साथ ही पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती होने के बाद 14 दिन से पहले छुट्टी लेकर जाने वाले बच्चों के मामलों की समीक्षा करते हुए उनकी विगत तीन माह की पोषण स्तर संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11, असातपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001 (उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी, डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991

RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

इयँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरियों को किया सम्मानित



क्यूँ न लिखूँ सच /ब्यूरो/ बरेली। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस सहयोग एवं अपराध नियंत्रण में सराहनीय योगदान देने वाले प्रदेश के 68,000 ग्राम प्रहरियों का सम्मान मंगलवार को पुलिस लाइन में किया।

योगी सरकार में प्रदेश के 68 हजार ग्राम प्रहरियों का मानदेय एक हजार रुपये बढ़ाने के साथ ही उनके परिवारों को पांच लाख रुपये सालाना कैशलेस इलाज की सौगात दी। ग्राम प्रहरियों के मानदेय में एकमुश्त 40 प्रतिशत की वृद्धि से अब उन्हें 2500 के बजाय 3500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। प्रत्येक ग्राम प्रहरी को सालाना 12 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 में ग्राम प्रहरियों को महज 1500 रुपये

1.28 करोड़ के घोटाले में एक्सईएन से स्पष्टीकरण तलब, 12 दिन बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं

क्यूँ न लिखूँ सच /ब्यूरो/ बरेली। लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड भवन में 1.28 करोड़ के एरियर घोटाले में अधिशासी अभियंता अब्दुल सत्तार से जवाब तलब किया गया है। इस मामले में तहरीर देने के 12 दिन के बाद भी

एफआईआर दर्ज नहीं होने से विभागीय अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड भवन में जालसाजों ने अधिकारियों-कर्मियों के फर्जी हस्ताक्षर कर 22 कार्मिकों के अवशेष वेतन-एरियर भुगतान के नाम पर 1.28 करोड़ रुपये निकाल लिए थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 16 लोग कभी भी विभाग/खंड में कार्यरत नहीं रहे हैं। मामला खुलने के बाद विभाग ने थाना कोतवाली में अज्ञात व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए एक अक्टूबर को तहरीर दी थी। 12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुए है। पुलिस ने विभाग से एफआईआर के विषय में जो भी सवाल किए, उसका कोई ठोस उत्तर नहीं दिया गया है।

बरेली कॉलेज में मूल्यांकन धांधली

पर गणित के 3 प्रोफेसर नपे

क्यूँ न लिखूँ सच /ब्यूरो/ बरेली। बरेली कॉलेज में बीएससी छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन और असाइनमेंट में कथित गड़बड़ी के आरोप में गणित विभाग के तीन शिक्षकों को निर्लंबित कर दिया गया है। निर्लंबित शिक्षक-पूर्व विभाग प्रभारी प्रो. स्वदेश सिंह, प्रो. पूम सिंह और डॉ. हनुमान वर्मा। कार्रवाई का आधार डॉ. आरिफ नवीन की शिकायत के बाद प्रो. सुभाष मेहरा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट। आरोप- बिना मूल्यांकन अंक पोर्टल पर चढ़ाने की अनियमितता। वहीं, प्रो. स्वदेश सिंह का दावा है कि प्रक्रिया



नियमानुसार ही अपनाई गई थी, केवल कुछ अंकों की शिकायत थी। नई नियुक्तियां कार्रवाई के बाद प्रो. पीएस चौधरी को गणित विभाग और प्रो. पीपी सिंह को भौतिकी विभाग का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। नया मोड़- कार्रवाई के बीच क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रो. आरके गोस्वामी ने कॉलेज में प्रबंध समिति के अनावश्यक हस्तक्षेप और प्रशासनिक दखल को लेकर सचिव व प्राचार्य से 10 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांग लिया है।

मेला कमेटी अध्यक्ष पद एवं चांदी के हिसाब को लेकर अमरिया में खूनी संघर्ष

क्यूँ न लिखूँ सच / कस्बा अमरिया में सोमवार रात हुए हत्याकांड की वजह रामलीला कमेटी में चंदे का हिसाब किताब रहा अध्यक्ष के पद की लड़ाई एवं चंद्र के हिसाब को लेकर दो पक्षों में आपसी विवाद चल रहा था जिस विवाद को लेकर दिनांक 12-10-26 को देर रात लगभग 9-30 पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया जिसमें तीन लोगों की मृत्यु हुई और दो लोग घायल हो गए मेला कमेटी की अध्यक्षता को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद पहले से थे पहले नरेश गुप्ता कमेटी के अध्यक्ष थे उनके निधन के बाद उनके चचेरे भाई चंद्रप्रकाश गुप्ता उर्फ चंदू लाल को मेल अध्यक्ष चुना गया दूसरे पक्ष के कौशल गुप्ता ने भी अध्यक्ष बने के लिए दावेदारी ठोकी थी इसलिए कौशल पक्ष की ओर से चंद्र प्रकाश गुप्ता से रामलीला कमेटी के चंदा की जानकारी व हिसाब मांगा जा रहा था

इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच रात खूनी संघर्ष की घटना हुई स्कूल संघर्ष में तीन लोग मारे गए जिसमें पूर्व मेला कमेटी अध्यक्ष स्वर्गीय नरेश गुप्ता के मंजिले बेटे रोहित गुप्ता उम्र 33 साल और उनके छोटे बेटे अंकित गुप्ता उम्र 26 साल की मृत्यु हो गई इस संघर्ष में एक राहगीर कुणाल श्रीवास्तव निवासी अमरिया उम्र 16 साल की भी मृत्यु हो गई कुछ समय पहले भी इसी बात को लेकर बैठक हुई थी पर उसे बैठक में वर्तमान अध्यक्ष चंद्रप्रकाश गुप्ता नहीं पहुंचे थे कौशल गुप्ता पक्ष के लोग बैठक में पहुंचे थे इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच रंजिश और गहरा गई इसके बाद 18 सितंबर को बैठक हुई जिसमें फिर मामला टल गया



◆ मृतक अंकित गुप्ता ◆ मृतक अंकित गुप्ता ◆ मृतक कुनाल

सोमवार रात अमरिया के एक बारात घर में चंद्रप्रकाश पक्ष के अमित गुप्ता ने दोनों पक्षों की बैठक बुलाई यह बातचीत के दौरान कहानी बड़ी तो बैठक समाप्त हो गई चंद्र प्रकाश पक्ष

पीलीभीत में रामलीला कमेटी विवाद पर ; मौके पर पहुंचे DIG अजय कुमार साहनी
क्यूँ न लिखूँ सच /ब्यूरो/ बरेली। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में हुए विवाद की शीलता को बरेली परिक्षेत्र अजय कुमार ने खुद कमान है। डीआईजी अजय कुमार साहनी, पुलिस अधीक्षक सुकोर्ति माधव के साथ सीधे ग्राउंड जीरो यानी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने वारदात स्थल का बारीकी से मुआयना किया और अब तक की पुलिसिया कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट तलब की। आपको बता दें कि यह पूरा विवाद रामलीला कमेटी के आपसी मतभेद के चलते शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष और फायरिंग में तब्दील हो गया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, उनका दर्द सुना और भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिलेगा। डीआईजी ने जांच अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि घटनास्थल से सभी वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं। विवेचना पूरी तरह निष्पक्ष, गहन और पुख्ता हो। वारदात में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा न जाए और उनके खिलाफ ऐसी कठोर कानूनी कार्रवाई हो जो मिसाल बने। घटना के तुरंत बाद पुलिस की तत्परता से फिलहाल अमरिया क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है ताकि माहौल पूरी तरह सामान्य बना रहे।

के लोग अपने घरों की ओर कौशल गुप्ता पक्ष के भी लोग अपने घर की तरफ लौट गए उसके बाद पूर्व मेला कमेटी

बरेली क्लब में सीएम योगी बोले- राष्ट्र निर्माता होते हैं शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी के लिए समर्थन में की जनसभा



क्यूँ न लिखूँ सच /ब्यूरो/ बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली क्लब में आयोजित शिक्षक सम्मेलन और जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि शिक्षक केवल सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता और युग निर्माता हैं।

जिस समाज में योग्य शिक्षक और आचार्य होते हैं, वह समाज दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। शिक्षक ही विद्यार्थियों को संस्कार, दिशा और योग्यता देते हैं। विद्यार्थियों की सफलता में गुरुजनों का सबसे बड़ा योगदान होता है। बरेली में शिक्षक निर्वाचन से जुड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश और देश

की पहचान उसकी शिक्षा व्यवस्था से होती है। एक समय उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था, लेकिन आजादी के बाद सरकारों के एजेंडे से शिक्षा हटती गई और इस क्षेत्र की उपेक्षा हुई।

इसका असर अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर भी पड़ा। वर्ष 2017 तक प्रदेश की पहचान का संकट खड़ा हो गया था और शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। मुख्यमंत्री ने उस दौर में भी शिक्षा की ज्योति जलाए रखने वाले शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में भाजपा सरकार बनने के समय बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग

में 1.60 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली थे। सरकार ने सबसे पहले नकलविहीन परीक्षा कराने पर जोर दिया। इसके बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। इससे प्रदेश के युवाओं को बिना भेदभाव सरकारी नौकरी मिलने का अवसर मिला। शिक्षकों को बताया समाज का मार्गदर्शक-योगी ने कहा कि जब कोई विद्यार्थी अपनी मेहनत और गुरु के मार्गदर्शन से मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करता है तो सबसे पहले गुरु के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करता है। शिक्षक समाज को संस्कारित करने के साथ राष्ट्र को नई दिशा देते हैं। उन्होंने भगवान श्रीराम, श्रीकृष्ण

कस्बे में तनाव का माहौल बन गया पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली एसपी हिमांशु गौरव और सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल समिति पुलिस बल ने घटनास्थल का जायजा लिया फायरिंग की घटना के बाद मृतकों के परिजनों में आक्रोश दिखाई दिया अचानक हुई वारदात से परिवार में चीख पुकार मच गई परिजनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे पुलिस ने रात में ही धड़ पकड़ शुरू कर दी वहीं आरोपी पक्ष की कर में भी तोड़फोड़ की गई कौशल गुप्ता के घर की छत से फायरिंग की गई पुलिस ने तीनों पार्थिव शरीर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया मृतकों के घर पर मातम छा गया है वहीं मृतक की मां ने खून का बदला खून से लेने की बात कही है रामलीला मेले में हर साल करीब 5 से 6 लाख रुपए का मुनाफा होता था इसी रकम के हिसाब मांगने को लेकर कौशल गुप्ता और वर्तमान मेल अध्यक्ष चंद्रप्रकाश गुप्ता के बीच तनातनी चल रही थी सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में हलचल मत गई मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए और खून के नमूने लेकर जांच के लिए सुरक्षित किया एसपी समिति अन्य पुलिस अधिकारी की घटना स्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया पुलिस विभाग घटना की वजह और फायरिंग की स्थिति की जांच में जुड़ गई है भाई कस्बे में माहौल तनाव पूर्ण रहा बाजार भी लगभग बंद रहा

प्रिय सुधि पाठको आप अपना यहाँ शुभकामना सन्देश (Birthday, anniversary, any kind of message) कम कीमत में विज्ञापन छपवाए - 9027776991

संक्षिप्त समाचार

बर्थ-डे पार्टी में बहा खून,

युवक की गला काटकर हत्या

क्यूँ न लिखूँ सच /ब्यूरो/ बरेली। एक बर्थ-डे पार्टी में खाने की मेज पर खून-खराब हो गया। एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड से पार्टी में भगदड़ मच गई। अफरात-तफरी का आलम बना रहा। गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। भारी संख्या में पुलिस पहुंची। हालत को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस लगाई है। युवक को हत्या से मृतक के घर में कोहराम मचा है, जबकि आरोपी का परिवार फरार है। घटनाक्रम शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गांव का है। मृतक की पहचान अर्जुन उर्फ पंकज के रूप में हुई है। सोमवार की शाम को गांव में एक बर्थडे पार्टी थी। दावत चल रही थी। इस बीच अर्जुन के भाई हरदेव और गांव के ही विशाल कोरी के बीच खाने को लेकर बहस हो गई। देखते ही देखते मारपीट होने लगी।

CM योगी के दौरे से पहले पुलिस ने भीम आर्मी के महानगर अध्यक्ष समेत कई नेता किए हाउस अरेस्ट

क्यूँ न लिखूँ सच /ब्यूरो/ बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली दौरे से ठीक पहले पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए भीम आर्मी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उनके घरों में नजरबंद



(हाउस अरेस्ट) कर दिया। इस कार्रवाई के चलते कलेक्ट्रेट पर होने वाला संगठन का प्रस्तावित महाधरना टल गया। तड़के 6 बजे घर पहुंची पुलिस- भीम आर्मी के महानगर अध्यक्ष शिवम भारती के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब छह बजे ही पुलिस उनके आवास पर पहुंच गई और उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया। भारती ने दावा किया कि उनके अलावा जिले भर में संगठन के लगभग 70 से 80 कार्यकर्ताओं को भी घरों में रोका गया। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की थी मांग- भीम आर्मी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी की थी। इसमें बहुजन समाज के लोगों से जुटने की अपील की गई थी, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। आवाज दबाना लोकतंत्र के लिए खतरा% कार्रवाई पर आक्रोश जताते हुए शिवम भारती ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। जनता की आवाज को इस तरह दबाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। शिवम भारती के अलावा अतुल वाल्मीकि (कार्यकारिणी सदस्य), अंकित सागर (तहसील अध्यक्ष मीरगंज), प्रभाकर जाटव (तहसील अध्यक्ष आंवला), खड़क सिंह (अध्यक्ष लीगल सेल), आदेश प्रताप, प्रताप सिंह और जसविंदर सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया।

IG रेलवे ने परखी GRP बरेली की तैयारी, दिए कड़े निर्देश

क्यूँ न लिखूँ सच /ब्यूरो/बरेली। आईजी रेलवे रामकृष्ण भारद्वाज ने जीआरपी थाना बरेली जंक्शन का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों, मालखाना, शस्त्रागार और बैरकों के व्यवस्थित रखरखाव का जायजा लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा की। निरीक्षण के समय महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली देखी और 'मिशन शक्ति' व 'ऑपरेशन मुस्कान' को पूरी संवेदनशीलता से चलाने के निर्देश दिए। हाईटेक निगरानी-बॉडी वॉन कैमरा, टैबलेट जैसे आधुनिक उपकरणों और यूपी पुलिस के 'यक्ष' ऐप के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर दंगा नियंत्रण उपकरणों और शस्त्र संचालन का जायजा लेकर अलर्ट रहने को कहा। लंबित मामलों का निपटारा-विवेचनाओं को समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश दिए। अंत में आयोजित सैनिक सम्मेलन में पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का भरोसा दिया गया। इस मौके पर एसपी रेलवे आशुतोष शुक्ला और डीएसपी विश्वजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।



आवेदकों के बीच पहुंचे कलेक्टर अंशुल गुप्ता , खड़े-खड़े सुनी समस्याएं

क्यूँ न लिखूँ सच / हाकम सिंह रघुवंशी/ जनसुनवाई में आवेदकों से किया सीधा संवाद, आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए निर्देश जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता आवेदकों के बीच पहुंचे और खड़े-खड़े उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान सभी आवेदक अपनी-अपनी कुर्सियों पर बैठे रहे। कलेक्टर ने आवेदकों से सीधे संवाद कर उनके आवेदनों की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता ने नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं को प्राथमिकता से सुनते हुए उनके निराकरण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई



करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का गंभीरतापूर्वक परीक्षण किया जाए और नियमानुसार समय-सीमा में उसका निराकरण सुनिश्चित किया जाए। आवेदकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक

रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए अधिकारी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करें। आवेदकों के बीच पहुंचकर सुनी समस्याएं –जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता का आवेदकों के बीच पहुंचकर खड़े-खड़े उनकी समस्याएं सुनना चर्चा का विषय रहा।

उन्होंने नागरिकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रकरणों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान आवेदकों को अपनी बात सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिला। कलेक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि जनसुनवाई केवल

आवेदन प्राप्त करने की औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से विचार करते हुए उसका उचित निराकरण किया जाना आवश्यक है। समय-सीमा में निराकरण पर जोर –कलेक्टर श्री गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए। जिन मामलों का निराकरण तत्काल संभव है, उनमें प्राथमिकता से कार्रवाई की जाए। वहीं, जिन प्रकरणों में जांच, विभागीय समन्वय अथवा अन्य औपचारिकताओं की आवश्यकता है, उनमें नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आवेदकों को प्रकरण की स्थिति से अवगत कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे आमजन की समस्याओं के

प्रति संवेदनशील रहें और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने में तत्परता दिखाएं। साथ ही, नागरिकों की शिकायतों के निराकरण में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। 1थमिकता – जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने इसी उद्देश्य के अनुरूप आवेदकों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला प्रशासन का प्रयास है कि जनसुनवाई के माध्यम से आम नागरिकों को अपनी समस्याएं रखने के लिए सुलभ मंच उपलब्ध हो तथा उनके आवेदनों पर पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत में जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित



क्यूँ न लिखूँ सच / पीलीभीत के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को आपदा प्रबंधन, आपदा जोखिम को कम करने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य दुष्यंत कुमार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपदा के समय जागरूकता, सतर्कता और सही निर्णय लेने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने युवाओं को आपदा से बचाव के उपायों की जानकारी प्राप्त करने, समाज में जागरूकता फैलाने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासन एवं राहत-बचाव दलों का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आपदा जोखिम को कम करने के लिए जनभागीदारी और पूर्व तैयारी आवश्यक है। महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर कविता कनौजिया ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं से होने वाले नुकसान को जागरूकता, सावधानी और उचित तैयारी के माध्यम से कम किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे आपदा से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और अपने परिवार तथा समाज को भी सुरक्षित रहने के प्रति जागरूक करें। वहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर गजेंद्र कुमार ने आपदा प्रबंधन में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आपदा के समय धैर्य बनाए रखना, सुरक्षा नियमों का पालन

करना तथा प्रशिक्षित राहत-बचाव दल के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को आपदा से पहले तैयारी रखने और आपातकालीन परिस्थितियों में जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की ओर से अरुण चौधरी (सहायक चालक), कुशल कुमार, शिवम कुमार एवं शिव चंद्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आपदा से

बचाव, जोखिम न्यूनीकरण और आपातकालीन सुरक्षा के प्रति जागरूकता पर जोर दिया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रोफेसर सत्येंद्र नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर राखी मिश्रा, दिवाकर सिंह एवं अनुपम कुमार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को आपदा के प्रति जागरूक रहने और सुरक्षित समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का संदेश दिया गया।

इको गार्डन में 50 हजार से अधिक संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के जुटने का दावा

समान कार्य-समान वेतन, नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन तेज

लखनऊ, क्यूँ न लिखूँ सच / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को लखनऊ के इको गार्डन में महाबैठक कर आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया। संघर्ष समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से कर्मचारी पहुंचे। संघर्ष समिति के अनुसार, इसमें 50 हजार से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों ने समान कार्य-समान वेतन, नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आउटसोर्स कर्मचारियों के समायोजन की मांग उठाई। संघर्ष समिति का कहना है कि एनएचएम कर्मचारी वर्षों से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का



अब तक समाधान नहीं हुआ है। समिति के अनुसार, मांगों को लेकर शासन स्तर पर वार्ता नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। इसी के चलते लखनऊ के इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों ने समान कार्य-समान वेतन लागू करने के साथ न्यूनतम 18 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देने, एनएचएम कर्मचारियों का नियमितीकरण कर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में समायोजन करने, रिक्त पदों पर तैनाती और पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की। इसके अलावा

कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रेज्युटी और स्वास्थ्य बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। आउटसोर्स कर्मचारियों को जिला स्वास्थ्य समिति अथवा प्रस्तावित आउटसोर्स सेवा निगम में समायोजित कर सेवा सुरक्षा और उचित वेतनमान देने की मांग भी उठाई गई। आंदोलन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर एकजुटता दिखाई। इनमें संयुक्त एनएचएम संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल गुप्ता, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ

के प्रदेश महामंत्री योगेश कुमार उपाध्याय, आरबीएसके संवर्ग के डॉ. आशुतोष उपाध्याय, सीएचओ संघ के प्रदेश अध्यक्ष हिमालय कुमार, नर्सिंग संवर्ग के हरिओम सिंह, एएनएम संघ की प्रेमलता पाण्डेय और काउंसलर संवर्ग के ज्योतिर्मय राय सहित विजय वाजपेयी, कमलेश कश्यप तथा अंबार जाफरी शामिल रहे। इसके अलावा फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्राविधिक, दृष्टि परीक्षण अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टीबी संवर्ग, दंत चिकित्सक और अन्य कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी आंदोलन को

समर्थन दिया। संघर्ष समिति ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करने में एनएचएम कर्मचारियों की अहम भूमिका है। इसके बावजूद उनकी मांगों का समाधान नहीं होना चिंता का विषय है। समिति ने शासन से कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने, शीघ्र वार्ता शुरू करने और मांगों के निस्तारण के लिए ठोस निर्णय लेने की अपील की। समिति ने स्पष्ट किया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक लखनऊ के इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदेशभर के संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों से आंदोलन में एकजुटता बनाए रखने का आह्वान भी किया गया। संघर्ष समिति के संयोजक अमित तोमर तथा मीडिया प्रभारी योगेश उपाध्याय ने कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में एकजुट होकर आंदोलन को मजबूत बनाने की अपील की।

संक्षिप्त समाचार शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, युवक गिरफ्तार

क्यूँ न लिखूँ सच / फतेहगंज पश्चिमी (बरेली)। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करते हुए जान से मारने की धमकी देने के मामले में फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, ग्राम लोहार नगला निवासी युवती की लिखित शिकायत पर 10 अक्टूबर 2026 को ग्राम सोरहा निवासी जुनैद (24) के खिलाफ मुकदमा संख्या 341/2026, धारा 69 और 351(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। युवती ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और शादी से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। मंगलवार, 13 अक्टूबर को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने कस्बे में हाईवे किनारे कहीं जाने के इंतजार में खड़े आरोपी जुनैद को गिरफ्तार कर लिया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक विनोद कुमार शर्मा कर रहे हैं। पूछताछ में आरोपी ने क्या बताया?—पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने युवती के साथ पिछले दो-तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग होने और फोन पर बातचीत के साथ शारीरिक संबंध होने की बात स्वीकार की। उसने मामले में अपनी सफाई अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में देने की बात कही। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ संबंधित मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष बने राहुल यदुवंशी

क्यूँ न लिखूँ सच / फतेहगंज पश्चिमी । अखिल भारतीय कुर्मी क्षात्रिय महासभा ने संगठन के मजबूत करने और समाज के लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी मीरगंज तहसील के नथपुरा निवासी समाजसेवी राहुल यदुवंशी को सौंपी है। उन्हें बरेली जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महासभा की ओर से राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक लाल बहादुर गंगवार को जिला संरक्षक, मनोज गंगवार को जिला महामंत्री और पूर्व वित्त एवं लेखाधिकारी राम आसरे गंगवार को जिला कोषाध्यक्ष बनाया गया है। संगठन की जिला इकाई गठित करने के साथ ही सभी ब्लॉकों में इकाइयां बनाने के निर्देश दिए गए हैं। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीएल गंगवार ने बैठक में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी दी। बैठक में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के रुहेलखंड मंडल प्रभारी हरीश गंगवार, मंडल महामंत्री डॉ. संजय पटेल, महेंद्र पाल सिंह और अमित गंगवार मौजूद रहे।

नवरात्रि के तीसरे दिन की गई मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना

बिलारी क्यूँ न लिखूँ सच / नगर और ग्रामीण क्षेत्र में शारदीय नवरात्रों पर भक्ति में वातावरण बना हुआ है। देवी मंदिरों में और घरों में हवन पूजा न संकीर्तन चल रहे हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई। इधर श्री राम आश्रम काली मंदिर सहसपुर बिलारी में चल रहे नवचंडी महायज्ञ में तृतीय दिवस मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के साथ यज्ञ मंडप में स्थापित देवताओं का पूजन किया। दुर्गा सप्तशती का हवन किया। हवन उपरांत मां दुर्गा की भव्य आरती एवं प्रसाद वितरण किया। मुख्य यजमान विशाल गुप्ता प्रीति गुप्ता, मुकेश अग्रवाल पूनम अग्रवाल रहे।



जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियां तेज, फील्ड ट्रेनर्स को दिए दिशा-निर्देश

क्यूँ न लिखूँ सच / जनगणना-2027 के द्वितीय चरण ‘जनसंख्या की गणना’ के अंतर्गत जनपद में नामित फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान जनगणना कार्य को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के साथ ही स्व-गणना, गोपनीयता के संरक्षण तथा नागरिकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार पर विशेष जोर दिया गया। प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिलाधिकारी अवनीश राय, अपर प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी गामिनी सिंगला तथा जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने फील्ड ट्रेनर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि जनगणना देश एवं समाज के विकास की योजनाओं के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जनकल्याणकारी योजनाओं, संसाधनों के नियोजन तथा विकास की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। इसलिए जनगणना कार्य से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारी



अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता, निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ करें। फील्ड ट्रेनर्स प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी को गणनाकर्मियों तक स्पष्ट एवं व्यावहारिक रूप में पहुंचाएं, ताकि कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। प्रशिक्षण में स्व-गणना को विशेष प्राथमिकता देते हुए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों को स्व-गणना की प्रक्रिया, उद्देश्य एवं महत्व के संबंध में सरल भाषा में जानकारी दी जाए और उनकी शंकाओं का समाधान किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसमें सहभागिता कर सकें। जनगणना के प्रति नागरिकों का विश्वास बनाए रखना तथा उन्हें सही एवं आधिकारिक जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है। अधिकारियों ने जनगणना के दौरान प्राप्त व्यक्तिगत सूचनाओं की गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि

गोपनीयता संबंधी निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए तथा किसी भी व्यक्ति की जानकारी अनधिकृत रूप से साझा न की जाए। साथ ही गणनाकर्मियों को नागरिकों के साथ शालीन, सहयोगात्मक एवं संवेदनशील व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षण के दौरान यह भी निर्देशित किया गया कि जनगणना के नाम पर नागरिकों से अनावश्यक रूप से कोई कागजात, प्रमाणपत्र अथवा अन्य दस्तावेज न मांगे जाएं। गणनाकर्म निर्धारित प्रश्नावली एवं अधिकृत प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य करें। नागरिकों के बीच किसी प्रकार की भ्रांति या अनावश्यक आशंका उत्पन्न न हो, इसके लिए सही जानकारी का प्रसार सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों ने सभी फील्ड ट्रेनर्स से अपेक्षा की कि वे प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त दिशा-निर्देशों को गणनाकर्मियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएं तथा जनगणना-2027 के द्वितीय चरण को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता, सूचनाओं की गोपनीयता और निर्धारित प्रक्रिया का पालन जनगणना कार्य की सफलता के प्रमुख आधार हैं।

ग्राम प्रहरियों को मा0 मुख्यमंत्री जी की सौगात, मानदेय 2,500 से बढ़ाकर 3,500; परिवार सहित मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस उपचार



क्यूँ न लिखूँ सच / बरेली में प्रदेश के 68 हजार ग्राम प्रहरियों के सम्मान कार्यक्रम का जालौन पुलिस लाइन में हुआ सजीव प्रसारण, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने ग्राम प्रहरियों के योगदान को सराहा ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और पुलिस को महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाने वाले ग्राम प्रहरियों के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी ने मानदेय वृद्धि और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण सौगातों की घोषणा की। ग्राम प्रहरियों का मानदेय 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये किए जाने के साथ ही उन्हें एवं उनके परिवारों को पांच लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा के लिए कैशलेस कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। इन कदमों से ग्राम प्रहरियों और उनके परिवारों को आर्थिक संबल तथा स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

नाथ नगरी बरेली में आयोजित कार्यक्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के 68 हजार ग्राम प्रहरियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद जालौन की

पुलिस लाइन में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया गया। इस दौरान सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, विज्ञान विशारद सी रोठिया पंचायत अध्यक्ष/प्रशासक, जिलाधिकारी समीर, पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे शिवानी सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं ग्राम प्रहरी उपस्थित रहे। सभी ने मा0 मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुना और देखा। ग्राम प्रहरियों का मानदेय 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये किए जाने से उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं, ग्राम प्रहरी एवं उनके परिवार के लिए पांच लाख रुपये तक के उपचार हेतु कैशलेस कार्ड की सुविधा स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के समय आर्थिक बोझ कम करने में सहायक होगी। मानदेय में वृद्धि और स्वास्थ्य सुरक्षा की यह पहल ग्राम प्रहरियों के कल्याण तथा उनके परिवारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ग्राम प्रहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और आमजन के बीच संपर्क की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

वे गांवों में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने, अपराधों की रोकथाम तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करते हैं। उनकी सतर्कता और समय पर दी गई सूचनाएं पुलिस को प्रभावी कार्रवाई करने में मदद करती हैं। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था में ग्राम प्रहरियों की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही पुलिस और ग्राम प्रहरियों के बीच बेहतर समन्वय, सतर्कता तथा जनसहयोग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया।

पत्रकार राज संघ में विनय पटेल को मिली राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार तिवारी ने तत्काल प्रभाव से डिजिटल मीडिया सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर की नियुक्त, संस्थापक नरेश राज शर्मा सहित मीडिया जगत और समाजसेवियों ने दी बधाई

क्यूँ न लिखूँ सच / जबलपुर, मध्य प्रदेश। पत्रकार राज संघ ने संगठन के प्रति निष्ठा, वफादारी और समर्पण को महत्व देते हुए जबलपुर निवासी विनय पटेल को डिजिटल मीडिया सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। पत्रकार राज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार तिवारी की ने विनय पटेल की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई है। इस नियुक्ति को संगठनात्मक मजबूती और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में संघ की गतिविधियों को नई दिशा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संगठन को उम्मीद है कि विनय पटेल अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे तथा संगठन के उद्देश्यों को आगे

शिक्षक निर्वाचन में शांतिपूर्ण मतदान कराने के निर्देश



क्यूँ न लिखूँ सच / मुख्य विकास अधिकारी गामिनी सिंगला ने मंगलवार को विकास भवन सभागार में बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की। बैठक में मतदान के लिए तैनात पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता, सतर्कता एवं समयबद्धता के साथ करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को

शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुचारु ढंग से संपन्न कराना सभी मतदान कर्मिकों की जिम्मेदारी है। जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान कार्य में लगाई गई है, वे सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण कर लें तथा निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने

मिशन शक्ति: कक्षा-9 की छात्रा अलशिफा बनीं एक दिन की सीडीओ

क्यूँ न लिखूँ सच / मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी गामिनी सिंगला के निर्देशन में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जगत की कक्षा-9 की छात्रा अलशिफा को एक दिन के लिए प्रतीकात्मक मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया। इस पहल के माध्यम से बालिका को प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझने तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर प्रदान किया गया। एक दिन की प्रतीकात्मक मुख्य विकास अधिकारी के रूप में अलशिफा ने जनपद में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की और प्रशासनिक कार्यों की प्रक्रिया को समझा। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं को प्रशासनिक व्यवस्था से परिचित कराना, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना तथा नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। मुख्य विकास अधिकारी



गामिनी सिंगला ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से बालिकाओं को सशक्त बनाने और उन्हें अपने भविष्य के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समझ विकसित करना है, ताकि वे भविष्य में अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप उच्च पदों पर

मतदान स्थल के प्रभारी के रूप में सभी व्यवस्थाओं की निगरानी सुनिश्चित करें। मतदान अधिकर्ताओं की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया, मतपत्र के पृष्ठभाग पर विशिष्ट पहचान चिह्न लगाने एवं पूर्ण हस्ताक्षर करने, टेंडर मतपत्र तथा चौलेंज मतों से संबंधित कार्रवाई को नियमानुसार संपन्न कराएं। इसके साथ ही मतपत्रों, आवश्यक प्रपत्रों, लेखा विवरण तथा अन्य लिफाफों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मतदान के दौरान निर्वाचन की शुचितता एवं गोपनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सभी मतदान अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न कराएं, जिससे बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

संक्षिप्त समाचार विदिशा विधायक ने भाजपा संगठन के सहयोग सेल के माध्यम से जनसमस्याएँ सुनी

क्यूँ न लिखूँ सच / हाकम सिंह रघुवंशी/ जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में विदिशा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री मुकेश टंडन ने पार्टी के सहयोग सेल के माध्यम से नागरिकों और कार्यकर्ताओं की समस्याएं के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में विदिशा के कार्यकर्ताओं, नागरिकों एवं व्यापारियों, ने अपनी समस्याओं को रखा। विधायक श्री मुकेश टंडन ने आवेदकों की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और समाधान हेतु निर्देश दिए। इस दौरान जिला भाजपा संगठन की ओर से सहयोग सेल में श्री मुकेश चौकसे,डा. राहुल जैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री कृष्ण कुमार गुप्ता,श्री दिनेश कुशवाहा ,श्री प्रशांत खत्री,श्री सुरेंद्र चौहान,श्री संतोष पेंटर,श्री कौशल अहिरवार सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे। भाजपा का सहयोग सेल जनता और प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करता है। संगठन के माध्यम से हर अंतिम व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना पार्टी की प्राथमिक संकल्पबद्धता है।

बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

क्यूँ न लिखूँ सच /पीलीभीत/उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से अाज जिलाधिकारी



आलोक कुमार की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण गांधी सभागार में प्रदान किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी देते हुए अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्वहन करने के संबंध में अवगत कराया गया। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मिकों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यवस्थित एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराना है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी सहित समस्त सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

छात्र ने जन्मदिन के मौके पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

क्यूँ न लिखूँ सच / फतेहगंज पश्चिमी- एक तरफ जहां युवा



पीढ़ी जन्मदिन के मौके पर सड़कों पर हुड़दंग और बाइक स्टंट करती नजर आती हैवहीं कस्बे के छात्र असद अंसारी ने अपने जन्मदिन पर पौधारोपण कर अनूठी पहल की। उन्होंने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। छात्र असद अंसारी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे जन्मदिन पर दिखावे और हुड़दंग के बजाय पौधे लगाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को शुभ अवसरों पर पौधारोपण कर उसकी देखभाल करनी चाहिए, ताकि पर्यावरण संतुलित रहे और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

Relationship Tips: Husband and wife must do these 7 things about money after marriage, otherwise problems may increase!

Sometimes, lack of clarity about income, expenses, savings, or debt can create tension in the relationship. A good way to avoid this is for both partners to discuss their financial priorities and responsibilities immediately after marriage. Life changes made, and many financial decisions have to be made, crucial for a husband and wife to communicate openly about income, expenses, savings, or debt can create to discuss their financial priorities and responsibilities that every husband and wife should consider together: clear information about each other's income. If both This makes it easier to create a household budget and set that their importance in the relationship is greater or less. in advance on rent, groceries, electricity, children's fees, based on their financial capabilities and circumstances. be fair to both. 3. How much should you save each month? together how much to save each month and for which help build financial security for emergencies and future discussion about home loans, personal loans, credit card amount, interest, and monthly installments can help financial pressures. 5. What are your future goals? - Every some may want to fund their children's education, while should share their goals and set timelines for them. This manage family financial responsibilities? Many families responsibilities. These topics should be discussed with much budget can be allocated to support the family so that household needs and other goals are not affected. 7. How will financial decisions be made? Spouses should decide how they will discuss major expenses, investments, loans, or other important financial decisions with each other. It can also be helpful for both to have a certain amount of money for their personal needs. Respecting individual financial independence while having shared financial goals can help build trust in the relationship.



significantly after marriage. Responsibilities increase, future plans are from running the household to children's education. Therefore, it is about money, along with love and understanding. Often, lack of clarity tension in the relationship. A good way to avoid this is for both partners immediately after marriage. Let's explore 7 important financial matters

1. How much do both of them earn? A husband and wife should have partners earn, discuss your monthly income and regular expenses openly. future goals. Just because one partner earns more or less doesn't mean
2. Who will cover household expenses and how? It's beneficial to agree and other essential expenses. Both partners can decide their contributions It's not necessary to split every expense equally; the arrangement should Saving for the future is not just about earning money. A couple can decide goals. Starting with a small amount is also beneficial. Regular savings plans.
4. Do you have any debt or EMIs? - After marriage, an honest balances, or other financial obligations is essential. Knowing the loan create a proper budget. This can also make it easier to manage unexpected couple's financial goals may be different. Some may want to buy a house, others may want to start a business or invest for retirement. Both partners can improve coordination in financial decision-making.
6. How will you also involve helping parents, supporting siblings, or other family respect and understanding. Both partners should be clear about how
7. How will financial decisions be made? Spouses should decide how they will

Tiffin Recipes: What to Give Your Husband in His Office Lunch Every Day? 7 Ideas That Will Make Him Quick and Fill His Tummy

What should you give your husband for lunch every day? The taste and aroma will make him happy as soon as he opens his lunch box. And it can be prepared quickly and effortlessly in your list of quick lunch recipes. The biggest morning is deciding what to put in his lunch or puri every day can often be boring. For both delicious and filling, and that it doesn't lunch preparer is also under tremendous prepared quickly and tastefully, with special preparation or expensive ingredients. healthy to make for your husband's office ideas that can be prepared in a short time. vegetables, and yogurt can make your lunch delicious, filling, and convenient for lunch at Poha is one of the easiest breakfasts to make tomatoes, peas, and carrots can make it adds flavor, protein, and good fats. A little in your tiffin. Paneer Paratha and Yogurt - than roti and vegetables, a paneer paratha stuffing the dough with paneer, onions, need to be cooked in too much oil or ghee. This makes for a balanced and filling lunch. rotis can be made into a delicious morning capsicum, carrot, and a little hung curd or

Vegetable Poha and Peanuts - quickly. Adding vegetables like onions, nutritious. Adding a few peanuts on top yogurt or fruit can be served with poha If your husband prefers a heartier lunch is a good option. Prepare the paratha by coriander, and mild spices. It doesn't Add yogurt and cucumber along with it. Vegetable Masala Roti Rolls - Leftover lunch. Add paneer or egg, onion, green chutney to the roti to make rolls. These are easy to pack in foil or butter paper and can be eaten at the office without any hassle. Moong Dal Cheela and Yogurt - Soaking moong dal overnight makes morning chores much easier. Grind it into a batter and add vegetables like onion, tomato, and coriander to it to make a chilla. Pack yogurt or mint chutney along with it. This is a protein-rich lunch and can help keep you full for a long time. Vegetable Upma - Upma is also a great quick office lunch. Prepare it by adding vegetables like carrots, peas, beans, onion, and capsicum to semolina or bread. Add peanuts or some roasted lentils to enhance both its taste and nutrition. Fruit or yogurt can be served alongside. Egg Bhurji Rolls - If you eat eggs, egg bhurji rolls are a great option for an office lunch. Add onion, tomato, and capsicum to two scrambled eggs and roll them in a roti or multigrain wrap. This is quick to prepare and provides a good amount of protein. Cucumber or any seasonal fruit can be included alongside. Vegetable Pulao and Raita - When you want something spicy and filling in your lunch, you can make a vegetable pulao. Mix vegetables like peas, carrots, beans, and capsicum with rice. If you have pre-cooked rice at home, it can be prepared even faster in the morning. Serving raita along with it makes for a more balanced lunch. Make your lunch more balanced - It's not just about filling your stomach, but also about nutrition. Try to include a protein source along with grains or rice in your lunch. Paneer, yogurt, eggs, lentils, chickpeas, or peanuts are easy options. Seasonal vegetables and fruits can also be included. Avoid packing excessively fried or spicy foods in your lunch box every day. Most importantly, choose a lunch box that's easy to eat and can satisfy hunger for a long time, even during a busy office schedule.



your list of quick lunch recipes. The biggest morning is deciding what to put in his lunch or puri every day can often be boring. For both delicious and filling, and that it doesn't lunch preparer is also under tremendous prepared quickly and tastefully, with special preparation or expensive ingredients. healthy to make for your husband's office ideas that can be prepared in a short time. vegetables, and yogurt can make your lunch delicious, filling, and convenient for lunch at Poha is one of the easiest breakfasts to make tomatoes, peas, and carrots can make it adds flavor, protein, and good fats. A little in your tiffin. Paneer Paratha and Yogurt - than roti and vegetables, a paneer paratha stuffing the dough with paneer, onions, need to be cooked in too much oil or ghee. This makes for a balanced and filling lunch. rotis can be made into a delicious morning capsicum, carrot, and a little hung curd or

Yoga Tips: A 10-Minute Yoga Routine for Women, Easy to Do at Home

Yoga can help keep the body active and relax. Doing yoga for a few minutes in the morning or at a convenient time during the day provides gentle stretching and movement. Importantly, many simple beginner-level exercises can be done at home it's often difficult for women to dedicate time to their health it's often impossible to find time for long workouts or a a day for yourself can help you practice simple yoga asanas active and feel relaxed. Doing yoga for a few minutes in provides gentle stretching and movement. Importantly, without any special equipment. However, it's important when performing yoga. If you feel pain, dizziness, or pregnancy, recent surgery, injury, or any other health instructor before beginning a yoga routine. Starting with position. Keep your spine comfortably straight and inhale relaxed. Bend your neck very slowly to the right and left. backward. Do not exert any force. Marjariasana and and knees. Inhale slightly, lift your chest forward, and and in sync with your breath. Balasana - 1 minute - Sit on forehead toward the mat. Keep your hands relaxed at the Adhomukha Svanasana - 1 minute - Using your hands and feet, bring your body into an inverted V shape. Don't force your heels to touch the ground. Beginners can bend your knees slightly if needed. Bhujangasana - 1 minute - Lie on your stomach and place your palms near your shoulders. Breathe in and gently lift your chest. Avoid overexerting your waist and rise only as much as your body can. Tadasana - 1 minute - Stand upright and balance your weight evenly on both feet. Raise your hands overhead and gently stretch your body. Hold this position for a few seconds, breathing normally. Shavasana and Relaxation - 2 minutes - Finally, lie comfortably on your back. Close your eyes and breathe normally. Relax your body and remain calm for a while. When should you do this 10-minute routine? Morning may be convenient for yoga, but if you don't have time in the morning, you can do some light yoga at any other time of the day. It's best to leave a sufficient gap between meals rather than immediately after a meal. Don't overstretch or overexert yourself while practicing yoga. Don't ignore pain. If you have a chronic illness, injury, pregnancy, or other health condition, consult your doctor or a qualified yoga instructor before starting a new routine.



without any special equipment. In today's busy lifestyle, and fitness. Between household and office responsibilities, trip to the gym. In such a situation, taking just 10 minutes and breathing exercises. Yoga can help keep the body the morning or at a convenient time during the day many simple beginner-level exercises can be done at home to consider your body's capacity and proper technique discomfort in any posture, stop immediately. In case of problem, it is best to consult a doctor or qualified yoga

Deep Breathing - 1 minute - Sit or stand in a comfortable slowly. Then exhale slowly. Keep your shoulders and face Then, gently rotate your shoulders forward and Bitilasana - 2 minutes - Come to the mat on your hands exhale, round your back. Perform the movement slowly your knees, bend your body forward, and bring your front or beside your body. This can be a relaxing position.

Jacqueline Fernandez: Delhi court grants actress relief! Can renew work visa

Actress Jacqueline Fernandez has been granted relief by a Delhi court. She can now renew her work visa. Let's find out the full story. A Delhi court has granted actress Jacqueline Fernandez a 'No-Objection Certificate' (NOC) to renew her work visa. Earlier in June, the court had framed charges against her, alleged fraudster Suresh Chandrashekhar, and 15 others in a ₹200 crore money-laundering case. What did the judge say? In an order dated October 6, Additional Sessions Judge Gagandeep Singh's court noted that the actress is a Sri Lankan citizen and has been living in India on an employment visa since 2009, which had expired. Considering Fernandez's application, the court noted that she is "actively working in the entertainment industry and has several professional commitments in India." Her presence is required to attend the ongoing hearing in the case. Actress tried to get visa issued - The court also noted that the actress had released her passport for re-issuance of visa from the Sri Lankan Consulate on February 20, 2025. The judge said, "The counsel for the accused or applicant has also stated that the Foreigners Regional Registration Office (FRRO) is not renewing the work visa without an NOC from the court." The court granted permission - Disposing of the application, the judge said, "Considering the facts and circumstances of the case, the applicant/accused Jacqueline Fernandez is granted an NOC to apply for renewal of her visa in accordance with law to the concerned authorities. The concerned authorities will consider the same independently in accordance with the law, rules, circulars and applicable bye-laws."



Bigg Boss 20: Who is Shannon K? News of her wildcard entry has created a stir; she has a special connection to Kumar Sanu.

Viewers may soon see the first wildcard entry in Bigg Boss 20. Shannon K's name is being widely discussed on social media. Let's find out who Shannon is. It's been a month since the Salman Khan-hosted show "Bigg Boss has seen a lot of action. Initially, 16 progressed, three contestants were some wildcard entries. Shannon K's social media. It's being reported that wildcard contestant this season. confirmation from the Bigg Boss team Shannon K's identity. Who is she? She Shannon K. is the daughter of singer has been married twice and has marriage. He adopted a daughter, made her debut with the pop single "A written by Justin Bieber's collaborator, Shannon K. is a singer, and her career In 2025, she performed at the world-has previously performed at London's has over 1.5 million subscribers. music. A significant portion of culture, which is why her music reflects Western pop. In 2026, she released the worth, bullying and emotional strength before. She has also worked as an but also an actress. She has taken acting cinema with the Hindi film 'Chal Zindagi'. Apart from this, she has also been associated with international projects. Her connection with Indian cinema has also been through music. She has sung a song for Oscar winning composer M.M. Keeravani in 'Tanvi the Great'. Apart from this, she has also lent her voice for the web series 'Salakar'.



20" began, and in this month, the show contestants participated. As the game eliminated. Now, the show may soon see name has been making the rounds on Shannon may enter the house as a However, there has been no official or Shannon herself. Let's explore has a special connection to Kumar Sanu. Bollywood singer Kumar Sanu. The a son, Jaan Kumar Sanu, from his first Shannon, with his second wife. Shannon Long Time," which was produced and Poo B. She performed at Coachella. isn't limited to the Indian music industry. renowned music festival, Coachella. She Royal Albert Hall. Her YouTube channel Shannon has trained in Indian classical Shannon's upbringing was in Western the influence of both Indian classical and song "Not My Shade." Topics like self-have been seen in Shannon's music actress - Shannon is not only a singer training in America. She entered Indian



The actress will become a mother for the second time at the age of 35, sharing the information with a beautiful photo.

Bollywood actress Kiara Advani is expecting her second child. The actress recently shared this information on social media. Kiara Advani and Sidharth Malhotra are expecting another baby. The couple shared this information on their social media handle, Instagram, on Wednesday morning. Fans and Bollywood celebrities have been pouring in to congratulate the couple. The couple shared a joint post with husband Sidharth Malhotra on Instagram. The post shows a photo of a baby wearing socks, with their daughter Saraya holding it. The caption of the post read, "Once again, blessed with the greatest gift." Our hearts are filled with love and gratitude.' Stars congratulated the couple - Rakulpreet Singh wrote on Kiara and Siddharth's post, "Wow, this is great news." Apart from these, many celebrities including Karan Johar, Parineeti Chopra, Athiya Shetty, Bhumi Pednekar, Kareena Kapoor and Masaba Gupta showered their love by congratulating them. Gave birth to daughter Saraya in 2025 - Let us tell you that Kiara and Siddharth welcomed daughter Saraya Malhotra in July 2025, almost two years after their marriage. Now, one and a half years after Saraya's birth, the couple is going to become parents again. Salman had said this to Siddharth - Some time ago, Siddharth Malhotra had come to promote his film 'The One' on the Weekend Ka Vaar episode of 'Bigg Boss 20'. During that time, the actor shared his experience of becoming a father with Salman Khan. Siddharth had said that being a father is the best role for him. Their daughter, Saraya, is now almost 15 months old and is learning new things. Salman Khan jokingly told Sidharth that he hoped they would welcome another baby soon. Sidharth smiled upon hearing this from the actor.